© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS | Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 03 , Issue : 08 | October – December 2017

वश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्थाः एक अध्ययन

Pradeep Kumar
Student (M.Com.)
Govt. P.G. College, Jind

Sachin
Assistant Professor,
D.G. College, Gurugram

सारांशः–

वैश्वीकरण विश्व में चारों और अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता हुआ एकीकरण है। वैश्वीकरण शब्द 1980 के दशक से आम बोलचाल की भाषा में आया है। वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया है। वैश्वीकण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की गति बढ़ी है। वैश्वीकरण के कारण ही भारत में नई औद्योगिक नीति 1991 में आई। वैश्वीकरण से भारत में विदेशी निवेश, आयात–निर्यात, खाद्यान्न, दूरंसचार का विकास, उद्योग, तकनीकी स्थानान्तरण आदि में वृद्धि हुई है।

ISSN 2454-308X
9 770024 543081

मुख्य शब्दः– वैश्वीकरण, अर्थव्यवस्था, विदेशी निवेश, आयात, निर्यात, भारत

परिचयः– बीसवी शताब्दी के अंतिम चरण की घटना भूमंडलीकरण को सशक्त बनाने और विस्तार करने के दृष्टिकोण से अतिमहत्वूपर्ण रही, जिसकी पृष्ठभूमि 1980 के आर्थिक संकट से तैयार हो रह थी। दो–ध्रुवीय व्यवस्था में एक ओर सोवियत संघ और दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्य था। सोवियत संघ के विघटन ने एक टुटे हुए बांध की भूमिका निभाई, जिसके बाद भूमंडलीकरण बाढ के पानी की तरह सभो जगह पहुँच गया। सोवियत संघ जैसे बांध को तोड़ने का श्रेय 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री को दिया गया, जिन्होंने ग्लास्नोस्ट (खुलापन) और पेरिस्त्रोइका (पुनर्निर्माण) के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपना भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक नई अर्थव्यवस्था की खोज की गई और उसे मजबूत बनाने के लिए उसके नेतृत्व में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और जी.ए.ए.टी. (General Agreements on Trade and Tariffs) के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन (World Trade organisation) को स्थापित किया गया। आर्थिक क्षत्रों में इन सब प्रयासों का उद्देश्य जिस नीति को लाना था, वह एल.पी.जी. अर्थात् उदारीकरण (Liberalization), निजीकरण (Privatization) और भूमंडलोकरण (वैश्वीकरण) (Globalization) के स्वरूप में थी।[1]

भारत की नयी आर्थिक नीति की घोषणा वर्ष 1991 में की गई। इस नीति में नए आर्थिक सुधारों, जिसमें मुख्यतः उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण शामिल हैं, को अपनाया गया है। इन आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को बहुत तीव्र करना तथा इसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने योग्य बनाना था। इस नीति में सरकार ने उत्पादों व सेवाओं के आयात व निर्यात पर लगे टैरिफ व गैर–टैरिफ के प्रतिबंधों को कम कर दिया है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेशक के लिए खोल दिया

© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS | Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 03 , Issue : 08 | October – December 2017

है। इन आर्थिक सुधारों के परिणामस्वरूप बहुत-सी विदेशी कंपनियों ने भारत में व्यावसायिक इकाइयां स्थापित की हैं, भारतीय व्यावसायिक इकाइयों को आधुनिक टेक्नोलॉजो उपलब्ध करवाई है, भारतीय उपभाक्ताओं को अधिक उत्पाद उपलब्ध करवा कर उनकी चयन क्षमता (Choice) को बढ़ाया है।[2]

वैश्वीकरण के दौर में भारत का आर्थिक विकास निःसंदेह प्रभावित हुआ है। आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें आर्थिक संवृद्धि भी निहित है। इसका अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके अन्तर्गत प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में लम्बी अवधि तक वृद्धि होती है। इसमें उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ तकनीकी एवं संस्थागत परिवर्तनों का होना भी आवश्यक है।[3]

अर्थः- भूमण्डलीकरण या वैश्वीकरण का अर्थ विश्व में चारों और अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता हुआ एकीकरण। यह एकीकरण मुख्य रूप से व्यापार तथा वित्तीय प्रवाहों के माध्यम से होता है। व्यापार तथा वित्तीय प्रवाह अर्थात् निवेश के साथ-साथ श्रमिकों तथा टेक्नोलॉजी का भी आवागमन अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार होता है।

भूमण्डलीकरण शब्द 1980 के दशक से आम बोलचाल की भाषा में आया है। घरेलू बाजार में जो बाजार शक्तियाँ क्रिया करती है, उन्हीं का राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर विस्तार ही भूमण्डलीकरण है।

वैश्वीकरण तभी संभव है जब ऐसे आदान-प्रदान के मार्ग में किसी देश द्वारा अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाय और इन्हें कोई ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था संचालित करे जिसमें सभी देशों का विश्वास हो और जो सर्वानुमति से नीति-निर्धारक सिद्धांतों का निरूपण करें, समान-नियम के अनुशासन में रहकर जब सभी देश अपने व्यापार और निवेश का संचालन करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वह एक ही धारा प्रवाहित होते हैं और यही वैश्वीकरण है।[4]

वैश्वीकरण का यह मानना है कि घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इससे विश्व की उच्चस्तरीय तकनीक, विशिष्ट ज्ञान, उत्पादकों व सेवओं आदि का घरेलू अर्थव्यवस्था में अंतरप्रवाह बढ़ेगा। विकसित देशों की पूंजी व टेक्नोलॉजी विश्व के विकासशील देशों; जैसे-चीन, भारत आदि में निवेश की जाएगी।[5]

भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जो वित्त-पूंजी के निवेश, उत्पादन और बाजार द्वारा राष्ट्रीय सीमा में ही वर्चस्वी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सीमा से परे भूमंडलीय आधार पर निरंतर अपना प्रसार करना चाहती है। इसका निर्णय-क्षेत्र सारी दुनिया है। यह अपनी मुद्रा के कार्य-क्षेत्र को निरंतर पुनः- पुनः समायोजित करती रहती है। किसी भी कंपनी की फैक्टरी आफिस और उसके कर्मचारी अधिक लाभ कमाने के लिए राष्ट्रीय सीमा के बाहर कहीं भी जाने को तैयार रहते हैं।[6]

उद्देश्यः-

(1) वैश्वीकरण के अर्थ को जानना व समझना।

(2) भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वैश्वीकरण के प्रभाव का आकलन करना।

शोध पद्धतिः– शोध–पत्र द्वितीयक डाटा पर आधारित है। डाटा प्रकाशित–पत्र, किताब, जर्नल, समाचार–पत्र, इंटरनेट साईट आदि से लिया गया है। शोध–पत्र में वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को विश्लेषणात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

परिणामः– वैश्वीकरण के कारण प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, विदेशी मुद्रा भण्डार, आर्थिक संवृद्धि दर, सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान सकल घरेलू पूँजी निर्माण (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में), सकल घरेलू बचत (सकल घरेल उत्पाद के प्रतिशत के रूप में), देश का निर्यात (परिमाणात्मक सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में) तथा शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Net F.D.I.) बढ़ा है। अतः वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर किया है।[7]

विदेशी निवेश में वृद्धिः– भारत में विदेशी निवेश में काफी बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 1990–91 में, कुल विदेशी निवेश 103 मिलियन US डॉलर था वर्ष 2009–10 में विदेशी निवेश बढ़कर 70,139 मिलियन US डॉलर हो गये। वैश्विक मंदी के कारण 2008–09 में विदेशी निवेशों के अंतरप्रवाह में कमी आई 2011–12 में विदेशी निवेश कम होकर 50,126 मिलियन US डॉलर रह गए। वर्ष 2012–13 में विदेशी निवेश का अंतप्रर्वाह बढ़ कर 64,443 मिलियन अमेरीकन डॉलर हो गया। विदेशी निवेश के अंतग्रर्वाह में वृद्धि से भारत के भुगतान शेष में सुधार हुआ है तथा विदेशी मुद्रा कोषों में वृद्धि हुई है।[8]

Foreign Direct investment inflows in India by Different countries (US $ millions)

Year	Foreign Direct Investment	Foreign Portfolio investment	Total
1990-91	97	6	103
1991-92	129	4	133
1992-93	315	244	559
1993-94	586	3567	4153
1994-95	1314	3824	5138
1995-96	2144	2748	4892
1996-97	2821	3312	6133
1997-98	3557	1828	5385
1998-99	2462(102.5)	61(-2.5)	2401(100.0)
1999-00	2155	3026	5181
2000-01	4029	2760	6789
2001-02	6130	2021	8151
2002-03	5035(83.7)	979(16.3)	6014(100.00)
2003-04	4322(27.5)	11377(72.5)	15699(100.00)
2004-05	6051	9315	15366
2005-06	8961	12492	21453
2006-07	22079	7003	29082

Note: Figure in bracket are percentage to the total in the row.

Source: Reserve Bank of India Bulletin, March 2008[9]

© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS | Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 03 , Issue : 08 | October – December 2017

निर्यात व आयात– विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा धीरे-धीरे बढ़ रहा है। मानव विकास सूचकांक (HDI) जो वर्ष 1990 में 0.389 था, बढ़कर वर्ष 2010 में 0.519 हो गया है। साथ ही, जीवन प्रत्याशा एवं साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई है।

Human development Report 2010 के अनुसार HDI रैकिंग की दृष्टि से 169 देशों में भारत का 119वां स्थान है।

इसी प्रकार देश का आयात (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में) वर्ष 1990–91 में 8.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2010 में 22.0 प्रतिशत हो गया है। निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) वर्ष 1990–91 में US $ 97 मिलियन था जो वर्ष 2010–2011 में बढ़कर US$ 30380 मिलियन हो गया है।

पण्य निर्याती में ठोस वृद्धि ने जहाँ चालू लेखा अधिशेषों के पीछे मुख्य संवाहक का कार्य किया है, वहीं विप्रेषणों(remittances) सहित विशेषकर निजी अन्तरणों के उत्प्लावक अदृश्य अन्तर्प्रवाह एवं साफ्टवेयर सेवा निर्यातों का भी उसे बनाये रखने में योगदान रहा है।

खाद्यान्न उत्पादनः– देश में खाद्यान्न उत्पादन जो कि वर्ष 1990–91 में 176.39 मिलियन टन था, बढ़कर वर्ष 2009–10 में 218.11 मिलियन टन तथा वर्ष 2010–11 में 241.56 मिलियन टन हो गया है। अतः खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बनाये रखने में वैश्वीकरण के कारण कृषि नीतियों में किये गये व्यापक परिवर्तनों की भूमिका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यद्यपि कृषि क्षेत्र की विकास दर लक्ष्य के अनुरूप प्राप्त नहीं हो पायी है, क्योंकि भारतीय कृषि आज भी मानसून पर मूलतः आधारित है। आर्थिक समीक्षा 2004–05, सारिणी 8.5(P.171) के अनुसार कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रकों में मूल्यवर्धित औसत वार्षिक वृद्धि दर आठवी योजना (1992–97) के दौरान 4.7 प्रतिशत से घटकर नौवी योजना 1997–2002 में 2.1 प्रतिशत हो गयी है।[10]

उद्योगों का विकासः– नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हाराव सरकार के वितमंत्री मनमोहन सिंह ने की। इस औद्योगिक नीति की केन्द्रीय विशेषता निजी क्षेत्र के हिस्सेदारी को बढ़ाना तथा लाइसेन्स परमिट राज को खत्म करना है।

नई नीति की घोषणा के समय 18 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। बाद में लाइसेंस वाले उद्योग की संख्या को और घटाकर पांच कर दिया गया है।

नई लघु औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अगस्त 1991 को की गयी। इस नीति के अन्तगत अतिलघु इकाइयों में पूंजी निवेश की सीमा 2 लाख से बढ़कर 5 लाख कर दी गयी। जिसे पुनः आबिद हुसैन समिति की सिफारिसों पर सरकार ने बढ़ाकर 25 लाख कर दिया।

सर्वाधिक उद्यम संख्या वाले पाँच राज्य

क्र.सं.	राज्य	उद्यमों की संख्या

1.	तमिलनाडू	4446999(10.56%)
2.	महाराष्ट्र	4874764 (10.39%)
3.	पश्चिम बंगाल	4285688 (10.71%)
4.	आन्ध्र प्रदेश	4023411 (09.55%)
5.	उ.प्र.	4015926(09.53%)

स्त्रोतः- भारतीय अर्थव्यवस्था 2010, पृ.52

दूरसंचार का विकास . वैश्वीकरण का एक प्रमुख आयाम सूचना संप्रेषण का तीव्र विकास रहा है। आज का युग सूचना क्रान्ति का युग कहा जाता है और सूचनाएं आदान-प्रदान करने में मोबाइल, टेलीवीजन, रोडियो, इंटरनेट आदि की महती भूमिका हैं अब महानगरों और छोटे-छोटे शहरों में नहीं बल्कि गांवों में भी दूरसंचार तेजी से फैल रहा है। 1948 में भारत में बसिक फोनों की संख्या 80 हजार थी। 1971 में भारत फोनों की संख्या 9. 80 लाख हो गई, 1981 में 21.5 लाख और 1991 में 50 लाख से ऊपर हो गई।

1991 में भारत में आर्थिक सुधार शुरू किये गये जिसमें उदारीकरण, नीजोकरण और वैश्वीकरण की त्रयी नीतिगत रूप से स्वीकार कर ली गई। इसके फलस्वरूप वर्ष 1994 में भारत की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा हुई। पिछले 15 वर्षों में भारत का जो आर्थिक विकास हुआ है, उसकी झलक सबसे आधिक संभवतः दूरसंचार क्षेत्र में दिखाई देती है।[11]

वित्तीय क्षेत्र पर प्रभाव- वैश्वीकरण वित्तीय क्षेत्र में अनेकों नवाचार (खोजें) हुए जिनका हमारे घरेलू क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। उभरते हुए विभिन्न वित्तीय संस्थानों तथा नियामक संस्थाओं ने वित्तीय क्षेत्र में रूढिवादी परम्पराओं को ताडकर एक गतिशील वित्तीय सेवा क्षेत्र को विकसित किया। इस प्रक्रिया में इस क्षेत्र को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस बदले हुए संदर्भ में भारतवर्ष में वित्तीय सेवा उद्योग को आगे आने वाले वर्षों में एक धनात्मक तथा गतिशोल भूमिका निभानी होगी।[12]

सांस्कृतिक प्रभावः- वैश्वीकरण की शुरूआत के समय से ही लोगों के मन में, खासकर विकासशील देशों के लोगों के मन में, यह भय व्याप्त रहा है कि पश्चिम का सांस्कृतिक वर्चस्व और फलस्वरूप स्थानीय संस्कृति का निस्तेज होना, अपरिहार्य है। लेकिन यह न तो वैश्वीकरण प्रक्रिया के पिछले बीस वर्षों के दौराने हुआ और न आज ही इस तरह का कोई संकट है। इसका कारण है कि संस्कृतियाँ पूरी तरह नष्ट नहीं होती बल्कि उनमें मात्र परिवर्तन होता है और वे अपना सह-अस्तित्व बनाए रखने में सफल होती हैं। परस्पर विरोधी संस्कृतियों स भी लोग बेहतर समायोजन रखते पाए जाते है।[13]

तकनीकी स्थानान्तरण प्रभाव- व्यापारिक खुलापन बढ़ने के कारण उत्पादन तकनीकी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने की प्रवृत्ति बढ़ी है। सामान्यतः पर्यावरण जागरूकता के कारण नई तकनीकी, पुरानी तकनीकी से ज्यादा हरित (ग्रीन) होती जा रही है। साथ ही विकसित देशों की उत्पादन तकनीकी से, कम विकसित देशों की उत्पादन तकनीकी अधिक हरित होतो है।[14]

निष्कर्षः– जो लोग भारत में वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणामों की चर्चा करते हैं, वे यह मानते हैं कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ने मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है। आर्थिक दृष्टि से भारत धीरे–धीरे शक्तिशाली आर्थिक सम्पन्न राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। भारतीय स्वाधीनता के बाद के तीस वर्षों में जो विकास दर थी, वैश्वीकरण के संपर्क में अभी पिछले तीस वर्षों में विकास दर और अधिक बढ़ी है। लोगों की बचत में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के बाद भारत में विदेशी निवेश बढ़ा हं। पिछले पन्द्रह वर्षों मे ंभारत के सामान्य जीवन स्तर में वृद्धि हुई है। जिन क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि हुई है। उनका संबंध आंतरिक संरचना से अधिक है। ऊर्जा, उपयोग और व्यपारिक सुविधाओं ने आर्थिक तथ्यों को बदला है। इसका परिणाम मध्यम वर्ग के आकार में वृद्धि भी है। बहुत से भारतीय व्यापारिक प्रतिष्ठान अब वैश्विक व्यापारिक प्रतिष्ठान है। मित्तल, टाटा, हिन्डालकों, विप्रो, क्राम्पटन ग्रीव्स, रैनबैक्सी आदि ऐसे ही व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं जो अब वैश्विक स्तर के प्रतिष्ठानों में गिने जाते हैं।[15] यदि अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण के पारस्परिक संबंधों की चर्चा करें तो कई सकारात्मक आधार उत्पन्न हुए हैं। विद्वानों का मानना ह कि इस युग में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। भारत के संबंध में प्रायः अर्थशास्त्रियों द्वारा कहा जाता है कि सकल घरेलू उत्पाद की दर और भी बढ़ सकती है।

संदर्भ सूची

1. यादव, राम गणेश (2014), भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लि0, नई दिल्ली, पृं0स0 102–103
2. Jain, T.R., Mukesh Trehan and Ranju Trehan (2014-15), व्यावसायिक वातावरण, VK Global Publications Pvt. Ltd. New Delhi पृं0स.–394
3. त्रिपाठी, राम प्रकाश मणि (2012), ''वैश्वीकरण और विकास'', धर्मेन्द्र प्रताप शाही (संपादक), वैश्वीकरण, विकास एवं पर्यावरण, फैजाबादः कोशल पब्लिशिंग हाऊस, पृं0 स0 –20
4. गुप्ता, सुभाष कुमार एवं सतीश कुमार उपाध्याय (2012), ''वैश्वीकरण एवं विकासः एक अध्ययन'', धर्मेन्द्र प्रताप शाही (संपादक), वैश्वीकरण, विकास एवं पर्यावरण, फैजाबादः कोशल पब्लिशिंग हाउस, पृं0 स.–261
5. Jain, T.R., Mukesh Trehan and Ranju Trehan (2014-15), व्यावसायिक वातावरण, VK Global Publications Pvt. Ltd. New Delhi पृं0स.–394
6. खेतान प्रभा (2010), भूमंडलीकरणः ब्रांड संस्कृति और राष्ट्र, नई दिल्लीः सामयिक, प्रकाशन, पृं0स. –15
7. त्रिपाठी, राम प्रकाश मणि (2012), ''वैश्वीकरण और विकास'', धर्मेन्द्र प्रताप शाही (संपादक), वैश्वीकरण, विकास एवं पर्यावरण, फैजाबादः कोशल पब्लिशिंग हाऊस, पृं0 स0 –21

8. Jain, T.R., Mukesh Trehan and Ranju Trehan (2014-15), व्यावसायिक वातावरण, VK Global Publications Pvt. Ltd. New Delhi पृं0स.-402
9. Shahi, C.K.P. and Amar Krishna (2012), " Review of Impact of Two Decades of Globalisations in India", धर्मेन्द्र प्रताप शाही (संपादक), वैश्वीकरण, विकास एवं पर्यावरण, फैजाबाद: कोशल पब्लिशिंग हाऊस, पृं0 स0 -58
10. शाही, धमेन्द्र प्रताप (2012), ''वैश्वीकरण एवं भारत का आर्थिक विकास: एक मूल्यांकन'', धर्मेन्द्र प्रताप शाही (संपादक), वैश्वीकरण, विकास एवं पर्यावरण, फैजाबाद: कोशल पब्लिशिंग हाऊस, पृं0 स0 -250-251
11. गुप्ता, सुभाष कुमार एवं सतीश कुमार उपाध्याय (2012), ''वैश्वीकरण एवं विकास: एक अध्ययन'', धर्मेन्द्र प्रताप शाही (संपादक), वैश्वीकरण, विकास एवं पर्यावरण, फैजाबाद: कोशल पब्लिशिंग हाउस, पृं0 स.-264, 265
12. जोशी, रोजी, संगम कपूर एवं आर.क. गुप्ता (2015), व्यावसायिक वातावरण, लुधियाना: कल्याणी पब्लिशर्ज, पृं0स. 21.8
13. सिंह, शिव बहाल, विकास का समाजशास्त्र (2016), जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स, पृं0 स.-190
14. शुक्ल, पी.सी. (2012), '' वृद्धिमान व्यापारिक खुलापन और पर्यावरण'', धर्मेन्द्र प्रताप शाही (संपादक), वैश्वीकरण, विकास एवं पर्यावरण, फैजाबाद: कोशल पब्लिशिंग हाउस, पृं0 स.-31
15. भार्गव, नरेश (2014), वैश्वीकरण: समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स, पृं0 स.-171.